



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 920 राँची, मंगलवार, 5 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

30 अक्टूबर, 2019

संख्या--5/आरोप-1-45/2018-26572 (HRMS)-- श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच, गृह जिला-लातेहार), के विरुद्ध इनके कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, चतरा के पद पर कार्यावधि से संबंधित दो आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रथम प्रपत्र-‘क’ उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-285/स्था०, दिनांक 28.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- कोषागार पदाधिकारी, चतरा के पद पर रहते हुए श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से०, के द्वारा बिना आवंटन के तीन विपत्रों को पारित कर कुल 8,18,88,204.00 रुपये की राशि निकासी कर जिला परिषद् कार्यालय, चतरा के पी०एल० खाते में हस्तांतरित किया गया, जो वित्तीय नियमावली एवं विभागीय निदेश का उल्लंघन है।

आरोप सं०-2-CAG के पत्रांक-38, दिनांक 02.12.2015 के द्वारा अनधिकृत राशि निकासी की सूचना प्राप्त होने पर अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से जिला अभियंता, जिला परिषद् चतरा से वस्तुस्थिति प्रतिवेदन की माँग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक-2730/वि०, दिनांक 16.09.2016 द्वारा कारण

पृच्छा किये जाने पर वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन विपत्र प्राप्त होने, कार्य की अधिकता तथा प्राधिकार पत्र समाप्त किये जाने संबंधित पत्र से भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के कारण भूलवश राशि निकासी किये जाने का प्रतिवेदन दिया गया तथा अविवेकपूर्ण एवं आधारहीन जवाब से वरीय पदाधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। यह अनुशासनहीनता एवं गलत मंशा से किया गया कृत्य है।

आरोप सं०-3- लेखा आपत्ति एवं वित्त विभाग द्वारा आपत्ति किये जाने पर जिला परिषद् कार्यालय, चतरा द्वारा राशि वापसी आंशिक रूप से की गयी। उक्त वापसी राशि में 14वें वित्त आयोग की राशि को भी विचलित कर वापस किया गया है, जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। बिना सक्षम आदेश के राशि के विचलन पर आपत्ति दर्ज नहीं किया जाना गलत मंशा से किया गया कृत्य है।

आरोप सं०-4- आरोपी पदाधिकारी द्वारा लोक व्यय और लोक निधि में सतर्कता नहीं बरती गयी, जिससे सरकारी धन की अनधिकृत निकासी संभव हुई एवं भारत सरकार की स्तर पर राज्य की छवि धूमिल हुई।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-4036, दिनांक 07.06.2018 द्वारा श्रीमती खाखा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। इसी बीच, श्रीमती खाखा के विरुद्ध एक अन्य आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-346/स्था०, दिनांक 31.05.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- कोषागार पदाधिकारी, चतरा के पद पर रहते हुए श्रीमती अमृता खाखा द्वारा जिला पंचायत शाखा का विपत्र संख्या-52/2015-16, सन्निहित राशि- 62,61,152/- तथा विपत्र संख्या-54/2015-16, सन्निहित राशि-18,03,552/- रुपये अनियमित तरीके से पारित किया गया। उक्त विपत्रों में संलग्न अभिश्रव निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत एवं पारित नहीं है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के हस्ताक्षर के बिना बिल के साथ प्रस्तुत अभिश्रव को मान्यता देना एवं आकस्मिकता विपत्र को पारित करना स्पष्ट रूप से वित्तीय नियमों की अनदेखी है एवं झारखण्ड कोषागार संहिता का उल्लंघन है।

आरोप सं०-2- विपत्र संख्या-52/2015-16 का सहायक के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है कि अभिश्रव पर DDO का हस्ताक्षर अपेक्षित है, परन्तु इस आपत्ति की अनदेखी करते हुए आरोपी पदाधिकारी द्वारा विपत्र को पारित कर दिया गया है, जो यह दर्शाता है कि जानबुझकर प्रश्नगत आकस्मिकता विपत्रों को पारित किया गया है। स्पष्टतः आरोपी पदाधिकारी द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई है।

आरोप सं०-3- जिला पंचायत शाखा का विपत्र संख्या-52/2015-16, राशि-62,61,452/- तथा विपत्र संख्या-54/2015-16, राशि-18,03,552/- रुपये में अनुमान्य कटौती यथा आयकर, विक्रय कर, vat की कटौती नहीं की गई थी। विपत्र की राशि को आपूर्तिकर्ता के खाता में सीधे अन्तरित न कर सरकारी खाते में अन्तरित की गई है, जो प्रभावी वित्तीय आदेशों के अनुकूल नहीं है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त बिन्दुओं पर बिना कोई आपत्ति किये विपत्र को अनुत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से पारित किया गया, जिससे सरकारी धन की क्षति हुई एवं जिससे स्थापित वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ।

आरोप सं०-4- विभिन्न विभागीय निदेशों द्वारा मार्च में कुल आवंटन का 15% राशि की निकासी की अधिसीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गई थी। लेकिन विभागीय आदेशों के अनदेखी करते हुए आरोपी पदाधिकारी

द्वारा पूरी राशि की निकासी कर ली गयी है, जो स्पष्टतः सरकार के आदेश के उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता है।

श्रीमती खाखा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की गंभीरता के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1757(hrms), दिनांक 23.08.2018 द्वारा इन्हें निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-1900(hrms), दिनांक 29.08.2018 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक-36, दिनांक 15.02.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्रीमती खाखा के विरुद्ध प्रथम प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोप सं०-1 एवं 4 को प्रमाणित तथा आरोप सं०-2 आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया एवं द्वितीय प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 2 एवं 3 को सही प्रतिवेदित किया।

श्रीमती खाखा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका बचाव-बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती खाखा के विरुद्ध संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित करने एवं इन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-2363(hrms), दिनांक 28.05.2019 द्वारा श्रीमती खाखा को निलंबन मुक्त किया गया तथा विभागीय पत्रांक-4330, दिनांक 31.05.2019 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती खाखा के पत्र, दिनांक 25.06.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(क) कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा कम्प्यूटर पर आवंटन चढ़ाया गया, जिसे लेखापाल द्वारा सत्यापित कर कोषागार पदाधिकारी के लॉगईन पर आया, जिसे देखकर इनके द्वारा विपत्र पारित किया गया।

(ख) इनके द्वारा पारित विपत्र सं०-52/2015-16 एवं विपत्र सं०-54/2015-16 में संलग्न अभिश्रव श्री सत्य प्रकाश, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा के द्वारा Sanctioned and passed वित्त किया गया था एवं श्री प्रकाश के प्रपत्र-‘क’ के आरोप उनके द्वारा समर्पित जवाब के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के द्वारा दिये गये मंतव्य एवं साक्ष्य में यह उल्लेखित किया गया है।

(ग) श्रीमती खाखा द्वारा कहा गया कि ये कोषागार के अलावा अन्य कई प्रभार में थीं, इसलिए प्रत्येक आपत्ति पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थीं।

श्रीमती खाखा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्रीमती खाखा द्वारा आवंटन आदेश की प्रति साक्ष्य के रूप में संलग्न नहीं की गई है, इसलिए इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण अमान्य है।

(ii) उपायुक्त, चतरा द्वारा विपत्र सं०-52/2015-16 के संबंध में कोई मंतव्य श्री प्रकाश द्वारा समर्पित जवाब में उल्लेखित नहीं किया गया है, अतः श्रीमती खाखा का यह कथन अमान्य है।

(iii) कोषागार पदाधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज करने के बाद भी उसे अनदेखा कर विपत्र पारित करने के संबंध में उनके द्वारा उल्लेखित किया गया कि वे कोषागार के अलावा अन्य कई प्रभार में थीं, इसलिए प्रत्येक आपत्ति पर हस्ताक्षर नहीं कर सकती थीं। उनका यह कथन ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः, समीक्षोपरांत श्रीमती खाखा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा अस्वीकृत करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMRITA KHAKHA 110031287102	श्रीमती अमृता खाखा, झा०प्र०से०, (चतुर्थ बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा-सह-प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
